

Sixteenth Loksabha

an&gt;

Title: Secreatry-General laid a copy of the President's address to both the Houses of Parliament assembled together on 29th January, 2018.

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 29<sup>th</sup> January, 2018.

**\*\*माननीय सदस्यगण**,संसद के संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सभी भारतीयों ने हाल ही में पोंगल,बिहु,लोहड़ी,मकर संक्रांति और वसंत पंचमी के उत्सव मनाए हैं। गणतंत्र दिवस भी हमारा एक प्रमुख उत्सव है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में,दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों की उपस्थिति ने, 'वसुधैव कुटुम्बकम्'की हमारी दीर्घदृष्टि में एक विशेष आयाम जोड़ा है।

2018 का वर्ष नए भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि यहां उपस्थित देश के कोने-कोने से आए सभी जनप्रतिनिधि,हमारे देश की विकास की इस महान यात्रा को और गति देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

**माननीय सदस्यगण**,हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर कहा करते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार,संविधान में निहित इसी मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है।

शायद ही किसी ने सोचा हो कि शौचालय निर्माण भी सामाजिक न्याय की इस भावना को बढ़ाने में सहायक होगा। शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा ही नहीं बचती बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय का एहसास भी होता है। सामाजिक न्याय का ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और व्यापक होता जा रहा है। हम सबका दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई जाए,तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें।

इस सदन में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक स्वयं देखा है कि महिलाओं को किस तरह लकड़ी बीनकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। महिलाओं और उनके बच्चों के पास धुएं भरी सांस लेने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। इस वजह से वे अनेक बीमारियां और कष्ट सहन करते थे। ऐसी गरीब महिलाओं को 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक

न्याय के एक अनदेखे पक्ष का समाधान किया है। अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

**माननीय सदस्यगण,** मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ-हानि का बंधक रहा। अब देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियाँ भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।

बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया है। मेरी सरकार ने Maternity Benefit Act में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित, 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के जीवन के सबसे नाजुक शुरुआती दिनों में, उनकी देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा।

**माननीय सदस्यगण,** गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली मेरी सरकार की योजनाओं से देश में आर्थिक लोकतंत्र और भी सशक्त हो रहा है। हम अब देश के बैंकिंग सिस्टम और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। 'जनधन योजना' के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

मेरी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है। अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं। 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।

लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं।

आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को मज़बूत करने के सरकार के ये प्रयास हमारे राष्ट्रीय जीवन को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। ये कोशिशें देश में नए तरह के सामाजिक संतुलन की स्थापना कर रही हैं जिसमें हर गरीब को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल रहा है।

**माननीय सदस्यगण,** किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं। सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

मेरी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, eNAM पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है।

दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है। दलहन और तिलहन क्षेत्र के उत्पादन बोनस के माध्यम से भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है।

किसानों की उपज, बाजार तक पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त न हो, देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी न हो, इस उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' शुरू की गई है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11 हजार करोड़ रुपए की 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि' के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।

मेरी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है। गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

**माननीय सदस्यगण,** गरीबों, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए, मेरी सरकार संवेदनशील और सक्रिय है।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

इसी तरह, मेरी सरकार ने गरीबों को एक रुपए प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर, बीमा योजनाएं सुलभ कराई हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है।

बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है। 'अटल पेंशन योजना' के तहत लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

**माननीय सदस्यगण**, एकात्म मानववाद के प्रणेता, दीन दयाल उपाध्याय के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, मेरी सरकार देश में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है।

देशभर में लगभग 2 लाख 70 हजार कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जो सस्ती दरों पर देश के दूर-दराज वाले इलाकों में भी विभिन्न सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी कर रहे हैं।

‘भारत नेट परियोजना’ के तहत, देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में एक लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। यह योजना e-health, e-education, e-governance और e-commerce को देश के हर गांव तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।

गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने और उन्हें विकास की राह पर चलने के लिए समर्थ बनाने के लिए, मेरी सरकार ‘सौभाग्य’ योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है।

मेरी सरकार, समाज के हर तबके तक विकास पहुंचाने की इसी सोच के साथ, ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना’ का कार्य और तेजी से आगे बढ़ा रही है। 2014 में केवल 56 प्रतिशत गांव ही सड़क संपर्क से जुड़े थे। अब 82 प्रतिशत से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं जिनमें से अधिकांश दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में हैं। हमारा लक्ष्य 2019 तक देश के प्रत्येक गांव को सड़क संपर्क से जोड़ देने का है।

हर गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाना अनिवार्य है। National Food Security Act के तहत देश के सभी राज्यों में सस्ती दरों पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था को पारदर्शी और लीकेज प्रूफ बनाया जा रहा है।

**माननीय सदस्यगण**, समाज के प्रत्येक कमजोर एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं सम्मान मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील मेरी सरकार ने ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है।

पिछड़े वर्ग में भी, अति पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नियुक्तियों का लाभ सुलभ कराने के लिए पिछड़े वर्ग के उपश्रेणीकरण के अध्ययन हेतु आयोग का गठन किया गया है।

आदिवासियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कई वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है।

देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों, खासकर उत्तर पूर्व में लाखों लोगों का जीवन, बांस से जुड़े उद्योग पर आधारित है। पेड़ की श्रेणी में रखे जाने के कारण, बांस का जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर पाना मुश्किल था। इन मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है। इससे, अब बांस को काटने, उसके परिवहन और उपयोग की स्वतंत्रता मिल गई है।

स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के बहुमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए देश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। ऐसे पहले संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में गुजरात में

नर्मदा के तट पर, सरदार सरोवर बांध के पास केवड़िया में रखी गई है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल और मणिपुर जैसे अन्य कई राज्यों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

**माननीय सदस्यगण,** हमारे देश में ढाई करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। मेरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके सशक्तिकरण और आर्थिक समावेश के लिए निरंतर कार्यरत है। सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' लागू किया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों में उन्हें 6 हजार से ज्यादा कैंप लगाकर, 9 लाख से अधिक आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

**माननीय सदस्यगण,** 'तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण' के संकल्प के साथ, मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है।

'सीखो और कमाओ'; 'उस्ताद'; 'गरीब नवाज कौशल विकास योजना'; 'नई रोशनी' आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्क्रीमों का लाभ भी दिया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।

**माननीय सदस्यगण,** सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। पहली बार मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए दो नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

**माननीय सदस्यगण,** गरीब और मध्यम वर्ग की एक बड़ी चिंता बीमारियों के इलाज से जुड़ी रहती है। इलाज के खर्च का आर्थिक आघात, बीमारी के आघात को और भी अधिक कष्टकारी बना देता है।

मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' बनाई है। इसके साथ ही 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' द्वारा योग-आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे आप सबके साथ यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि:

• 'प्रधानमंत्री जन औषधि' केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केन्द्रों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है।

ÿ 'दीनदयाल अमृत योजना'के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है।

ÿ दवाओं के साथ ही, हृदय रोगियों के लिए 'स्टेंट' की कीमत को 80 प्रतिशत तक कम किया गया है। घुटने के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट की कीमत को भी नियंत्रित किया गया है।

ÿ 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम'के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में, रियायती दरों पर सवा 2 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन किए गए हैं।

ÿ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए MBBS की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रेजुएट की 7 हजार से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं।

ÿ चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक' भी प्रस्तुत किया है।

ÿ मुझे यह बताते हुए खुशी है कि देश में टीकाकरण की जो वृद्धि दर पहले सिर्फ 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुआ करती थी, वह अब बढ़कर 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष पहुंच गई है। इससे, देश के दूर-दराज, विशेषकर आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी बहुत लाभ मिला है। हाल ही में मेरी सरकार ने 'Intensified Mission Indradhanush' भी शुरू किया है।

**माननीय सदस्यगण,** शिक्षा ही राष्ट्र के भविष्य-निर्माण का आधार है। मेरी सरकार, देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार द्वारा 'अटल इनोवेशन मिशन' के तहत 2,400 से ज्यादा 'अटल टिन्करिंग लैब्स' को स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डाली जा सके।

मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी'के गठन को मंजूरी दी है।

युवाओं के उज्वल भविष्य के लिए सक्रिय मेरी सरकार देश में 20 'इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेन्स' बनाने पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत चुने हुए शिक्षण संस्थानों को 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

सभी 'इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट' को और बेहतर बनाने के लिए स्वायत्तता देने वाला एक कानून भी बनाया गया है।

**माननीय सदस्यगण,** हमारा देश, दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए मेरी सरकार स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है।

युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास करने के लिए हाल ही में मेरी सरकार ने 'संकल्प' और 'स्ट्राइव' नाम की दो योजनाओं को स्वीकृति दी है।

जो उद्योग या कंपनियां नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही हैं उन्हें 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना'के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी इस योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

'नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम' से लगभग 5 लाख नौजवान लाभान्वित हो चुके हैं।

हमारे श्रमिक बंधु, राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार द्वारा, श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ, श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गयी है। अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं।

**माननीय सदस्यगण**, खेल-कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पूरे विश्व में विकास के एक मापदंड के रूप में देखा जाता है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग मेरी सरकार, खेल-कूद के क्षेत्र में भी देश की विश्व पटल पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है।

देश में बीते महीनों में फीफा Under-17 World Cup और Asian Athletic Championship जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ।

इससे खेल के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही है, आज देश के हर कोने में फुटबॉल जैसे खेलों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है।

मेरी सरकार ने 1,750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' नाम से एक महत्वाकांक्षी अभियान आरंभ किया है।

प्रतिभावान खिलाड़ियों के पारदर्शिता से चयन के लिए 'स्पोर्ट्स टैलेन्ट सर्च पोर्टल' भी शुरू किया गया है।

एक हजार प्रतिभावान खिलाड़ियों को मेरी सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्टाइपेन्ड देने की योजना प्रारंभ की गई है।

**माननीय सदस्यगण**, हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं, हमारी पहचान हैं और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को आधार देती हैं।

यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हाल ही में कुंभ-मेले को यूनेस्को द्वारा 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर'की सूची में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत की

पहली 'हेरिटेज सिटी' का दर्जा दिया गया है। चेन्नई ने भी संगीत की गरिमामय परंपरा के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में स्थान प्राप्त किया है।

'स्वदेश दर्शन' और 'अमृत योजना' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी सरकार ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने और उन्हें संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

**माननीय सदस्यगण,** देश के विकास के लिए, किसानों, मछुआरों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों तक सही समय में सही जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा में भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। जून 2017 में, भारत के GSLV MK-III की पहली developmental flight सफल रही जो कि देश की launch capability को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है।

पिछले वर्ष 5 मई को इसरो द्वारा दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी तकनीकी क्षमताओं के लाभों को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

इस वर्ष 12 जनवरी को इसरो ने PSLV-C40 का सफल प्रक्षेपण करके देश का मान बढ़ाया है। इसी दिन इसरो ने सौर्वे उपग्रह का प्रक्षेपण किया।

**माननीय सदस्यगण,** डिजिटल कनेक्टिविटी के आधुनिक दौर में हमारे देशवासी, हमारी भावी पीढ़ी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग कर सके, इसके लिए मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। Digital India मिशन, गरीबों एवं वंचितों को सम्मानपूर्वक उनका अधिकार दिलाने के लिए, एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अंतर्गत मेरी सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक एक करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में 'भीम App' बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए 'उमंग App' द्वारा सौ से ज्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।

आधार द्वारा गरीब लाभार्थियों को, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, बिना बिचौलियों के, सीधे पहुंच रही हैं। वर्तमान सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकारी लाभ सही व्यक्ति को मिलना संभव हुआ है और अब तक 57 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के कारण अब देश में 113 मोबाइल कंपनियां कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 2014 में मात्र 2 थी। इससे देश के छोटे शहरों में भी हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।



**माननीय सदस्यगण**, देश के संतुलित विकास में डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी, दोनों की ही बड़ी भूमिका है। मेरी सरकार 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार देश के परिवहन क्षेत्र को तैयार करने और संपर्क बढ़ाने पर कार्य कर रही है। आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं इस तरह विकसित की जा रही हैं कि सभी यातायात सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों।

रेलवे आज भी देश में यातायात का प्रमुख साधन है और इसलिए रेलवे में क्षमता विकास और आधुनिकीकरण के लिए निवेश में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। मेरी सरकार विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के लिए वचनबद्ध है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

मेरी सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी एक नई नीति बनाई है। नई नीति में 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' पर जोर दिया गया है। देश में, अभी 11 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

हाल ही में मेरी सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के एक नए वृहद कार्यक्रम 'भारतमाला' को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत, National Corridor Efficiency में वृद्धि करने के लिए लगभग 53 हजार किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग चिह्नित किए गए हैं।

'जलमार्ग विकास परियोजना' के अंतर्गत गंगा नदी पर वाराणसी, साहिबगंज, फरक्का और हल्दिया में प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

'सागरमाला कार्यक्रम' के अंतर्गत, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में विशेष आर्थिक ज़ोन और पारादीप एवं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट पर 'Smart Port Industrial Cities' का कार्य आरंभ हो गया है।

देश के छोटे शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकें और निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और युवा कम खर्च पर, आसानी से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें, इसके लिए 'उड़ें देश का आम नागरिक' यानी, 'उड़ान' योजना शुरू की गई है। स्वतन्त्रता के बाद देश में जहां केवल 76 हवाई अड्डे ही वाणिज्यिक उड़ानों से जुड़े थे वहीं 'उड़ान' योजना के मात्र 15 महीनों में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया है। अब तक 16 ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू भी हो चुकी हैं।

इन योजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ-साथ देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

**माननीय सदस्यगण**, पहली बार ऐसा अवसर आया है जब देश में बिजली क्षमता के विस्तार में लक्ष्य से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब भारत बिजली का net exporter बन गया है।

मेरी सरकार ने 'One Nation, One Grid' का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मज़बूत करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं। 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है।

‘उजाला योजना’ के अंतर्गत अब तक देश में 28 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा भी 50 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब की बिक्री की गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में सालाना 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ यूनिट बिजली की बचत भी हो रही है।

बिजली बचाने के अभियान के साथ ही, देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने का कार्य भी जारी है। पिछले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है।

भारत के प्रयास से International Solar Alliance एक विधायी निकाय बन चुका है। इसका मुख्यालय भारत में ही स्थापित किया गया है।

**माननीय सदस्यगण,** देश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास का लाभ पहुंचाने की दृष्टि के साथ, मेरी सरकार उत्तर-पूर्व के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए हाल ही में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता वाली North East Special Infrastructure Development Scheme को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत पेयजल, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों में, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है।

हाल ही में, मिजोरम में 913 करोड़ रुपए की लागत से बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व में संपर्क मार्ग बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है।

अगरतला-आखुरा रेल-लिंक पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा।

शिलॉन्ग-तुरा रोड प्रोजेक्ट का पिछले वर्ष दिसंबर में लोकार्पण किया गया है। इस सड़क से पूरे ‘उत्तर-पूर्व’ क्षेत्र में सड़क संपर्क सुधारने में मदद मिलेगी।

पिछले वर्ष देश के सबसे लंबे नदी पुल ढोला-सादिया को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस पुल ने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है।

मेरी सरकार द्वारा बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-16 के तौर पर विकसित करने का फैसला भी लिया गया है।

**माननीय सदस्यगण,** केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के नियमित प्रयासों के कारण, देश की आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर में, सुरक्षा स्थिति में भी बदलाव आया है। नक्सली-माओवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है। इसके लिए इन क्षेत्रों के जागरूक निवासी और हमारे सैन्य, अर्ध सैन्यबल और हमारे पुलिस बल बधाई के पात्र हैं। हम अपने उन सभी प्रहरियों की सराहना करते हैं और जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी हिंसा, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ से सीधे-सीधे जुड़ी है। हमारे सैन्य और अर्ध सैन्य बल तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस हिंसा का उपयुक्त जवाब दे रहे हैं।

मेरी सरकार ने उन लोगों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा है जो हिंसा छोड़ना चाहते हैं और भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। नक्सली-माओवादी विचारधारा से प्रभावित युवा, पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक संख्या में समर्पण करके मुख्यधारा में आए हैं।

हाल ही में मेरी सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है।

डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में Strategic Partnership से संबंधित नीति को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे प्रमुख Defence Platforms और Equipments के निर्माण में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

मेरी सरकार ने 'One Rank One Pension' के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है।

**माननीय सदस्यगण,** मानवता की सेवा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रहा है। चाहे नेपाल में भूकंप हो या श्रीलंका में बाढ़ की आपदा, या मालद्वीप में पेयजल का संकट, इन्हीं मूल्यों के कारण भारत हमेशा First Responder के रूप में उपस्थित रहा है।

आज विश्व के किसी भी कोने में बसे सभी भारतीयों को यह भरोसा है कि वे कहीं भी संकट में पड़ेंगे तो उनकी सरकार उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश वापस ले आएगी। वर्ष 2014 के बाद से विदेश में संकट में फंसे 90 हजार से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है।

मेरी सरकार के सफल राजनयिक प्रयासों के कारण, विश्व में भारत को एक नया सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके फलस्वरूप International Tribunal for the Law of the Sea, International Maritime Organisation और Economic and Social Council में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। International Court of Justice का चुनाव तो काफी रोचक रहा जिसमें अंततोगत्वा भारत ने सफलता पाई।

पिछले वर्ष Missile Technology Control Regime में शामिल होने के पश्चात् भारत को इस वर्ष Wassenaar Arrangement और Australia Group में भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह सफलता लंबी जद्दोजहद और लंबे इंतजार के बाद मिली है और मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

चाबहार पोर्ट का प्रारम्भ होना एक ऐतिहासिक घटना है। इस पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी गयी है। इस वर्ष भारत-अफगानिस्तान के बीच हवाई-गलियारे की शुरुआत भी हुई है, जिसमें माल-ढुलाई का कार्य आरम्भ हो गया है।

विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ देश का जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है। इस वर्ष 9 जनवरी को 'प्रवासी भारतीय दिवस' के अवसर पर पहली बार प्रवासी भारतीय सांसदों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 24 देशों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग मंत्रालय के साथ मिलकर देश में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार करने का एक वृहद कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 251 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 60 केन्द्र काम करना शुरू कर चुके हैं।

**माननीय सदस्यगण,** देश के विकास को और अधिक ठोस आधार देने के लिए मेरी सरकार ने आर्थिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम प्राथमिकता के तौर पर किया है।

इसी का परिणाम है कि धीमी वैश्विक आर्थिक विकास दर के बावजूद, भारत की विकास दर प्रभावशाली रही है। अर्थव्यवस्था में, 2016-17 की पहली तिमाही से, जीडीपी विकास में अस्थायी मंदी रही। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में इस गिरावट में बदलाव आया। पिछले साढ़े तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट औसतन कम हुए हैं।

वर्ष 2017 में विदेशी मुद्रा भंडार 410 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर चला गया। मेरी सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पिछले तीन वर्षों के दौरान 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

**माननीय सदस्यगण,** नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पिछले तीन वर्षों में 1,428 अनावश्यक कानून समाप्त किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

ठोस और समावेशी विकास की दिशा में, मेरी सरकार ने देश में ईमानदारी को संस्थागत करने का महत्वपूर्ण काम किया है और पारदर्शी व्यवस्थाओं की स्थापना कर रही है।

देश के आर्थिक एकीकरण के लिए, मेरी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स-सुधार, Goods and Services Tax के रूप में किया है। कीमतों के कम होने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, इसके लिए मेरी सरकार द्वारा National Anti-Profiteering Authority का गठन भी किया गया है।

मेरी सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का री-कैपिटलाइजेशन करने का निर्णय भी किया गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में लगभग साढ़े 3 लाख संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।

सरकारी खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अधिकतम उद्यमियों को अवसर देने के लिए मेरी सरकार ने, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानि Gem नाम की एक नई व्यवस्था स्थापित की है। Gem पोर्टल की मदद से देश का छोटे से छोटा उद्यमी भी सरकार को अपना उत्पाद बेचने में सक्षम हुआ है।

सरकारी खरीद में Make In India को प्राथमिकता देने के लिए नई नीति बनाई गई है। इस नीति से घरेलू उत्पादों के निर्माण और सेवाओं में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

केन्द्र सरकार, व्यापार के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है।

मेरी सरकार की इन कोशिशों के कारण ही तीन वर्षों में भारत, वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैंकिंग में 142 से 100वीं रैंक पर पहुंच गया है। इससे विश्व बाजार में देश की साख और बढ़ी है।

**माननीय सदस्यगण,** मेरी सरकार का प्रयास जनभागीदारी द्वारा जनकल्याण करने का है। मेरी सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों के साथ बातचीत करके तथा सिविल सोसायटी के लोगों के साथ भी चर्चा करके उनके सुझावों को नीतियों-निर्णयों में शामिल कर रही है।

**माननीय सदस्यगण,** देश में गवर्नेंस के प्रति सजग लोगों में, देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से, अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। बार-बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो बढ़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए।

**माननीय सदस्यगण,** राष्ट्र निर्माण एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें देश के हर व्यक्ति की अपनी-अपनी भूमिका है। हम सभी का कर्तव्य है कि देश के सम्मुख अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करें। राष्ट्र निर्माण से जुड़े लक्ष्य समय पर पूरे हों, यह दायित्व हम सभी का है।

2022 में, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तब तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के सपने पूरा करेगी बल्कि नए भारत का आधार भी मजबूत करेगी।

नए भारत का सपना किसी एक राजनीतिक दल या संगठन का नहीं है। यह देश के 130 करोड़ लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। इस सपने को पूरा करने के लिए, हम सभी को मिलकर पूरे समर्पण के साथ काम करना होगा।

आइए, हम सब मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक साथ चलें, एक दिशा में चलें, एक निष्ठा से चलें, और भव्य भारत के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।

जय हिन्द !

**Honourable Members,** I welcome you all to the Joint Sitting of the Two Houses of Parliament. We have all recently celebrated the festivals of Pongal, Bihu, Lohri, Makar Sankranti and Vasant Panchami. For us, the Republic Day is also a major festival. The presence of Heads of States and Governments of ten ASEAN countries during this year's Republic Day celebrations added a special dimension to our vision of 'Vasudhaiv Kutumbakam'.

2018 is an important year for realising our vision of a New India. I am confident that peoples' representatives present here, who have come from different parts of the country, would play an active role in accelerating this great journey for the development of our nation.

**Honourable Members,** the architect of our Constitution, Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar used to say that political democracy cannot survive without social and economic democracy. Guided by this fundamental spirit of the Constitution and committed to the welfare of weaker sections, my Government is working towards strengthening social justice and economic democracy and to usher ease of living for the common man.

Perhaps no one had imagined that construction of toilets could also contribute towards social justice. Construction of toilets not only protects their dignity but also fosters a feeling of social justice in women. The movement for social justice is becoming widespread day by day. It is our collective responsibility to pay a befitting tribute to Pujya Bapu by making the country Swachh by 2019 when we celebrate the 150<sup>th</sup> birth anniversary of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi.

Here in this House, there are many like me who for years have seen women collecting firewood for cooking. They and their children had no option but to endure the ill effects of smoky kitchens causing disease and suffering. 'Pradhan Mantri Ujjwala Yojana' has empowered these poor women to enjoy equal rights with their privileged counterparts thereby addressing a hitherto ignored aspect of social justice. So far, under this scheme, over 3 crore 30 lakh cooking gas connections have been provided.

**Honourable Members**, for decades, the dignity of Muslim women has remained captive to political cost-benefit. Now the Nation has an opportunity to emancipate them from this situation. My Government has tabled a Bill on Triple Talaq in Parliament. I hope that the Parliament will soon pass it into a law. The law on Triple Talaq, once enacted, will also enable Muslim sisters and daughters to live a life of self-respect with courage.

To eradicate discrimination against daughters, my Government had introduced the 'Beti Bachao Beti Padhao' scheme. Seeing its positive results, the scheme has been extended from 161 districts to 640 districts.

The Government has also taken a big step by amending the Maternity Benefit Act. It now provides for 26 weeks of paid leave in place of 12 weeks. Working women will now be able to devote more time towards their new born children during their crucial formative years.

**Honourable Members**, my Government which feels for the poor is implementing schemes for further strengthening economic democracy in the country. We are moving towards bridging the gap between the country's banking system and the poor completely. Under the 'Jan Dhan Yojana', so far, about 31 crore bank accounts have been opened for the poor. Women have especially benefitted from the scheme with the percentage of Savings Bank accounts held by them going up to more than 40 per cent from the earlier 28 per cent.

To make bank credit accessible to the poor and middle class and to encourage self-employment, my Government has facilitated provision of credit without insisting on bank guarantee. Through easy access to credit, people are now able to fulfil their dream of setting up their own enterprise. Under the 'Pradhan Mantri Mudra Yojana', about 10 crore loans have been sanctioned so far and more than Rs. 4 lakh crore worth of loans have been disbursed. About 3 crore first time beneficiaries have received assistance under this scheme for self employment.

The endeavour of the Government towards strengthening economic and social democracy is helping redefine our national life. These efforts are establishing a new social order in the country which provides equal opportunity to the poor to march ahead.

**Honourable Members,** the highest priority of my Government is to remove various difficulties faced by farmers and to raise their standard of living. The schemes of my Government are not only removing their hardships but also reducing the expenditure incurred by them on farming.

As a result of Government's policies and the hardwork of farmers, a record production of more than 275 million tonnes of food grain and about 300 million tonnes of horticultural produce has been achieved in the country.

My Government is committed to doubling of farmers' income by 2022. To ensure remunerative price to the farmers for their produce, the agriculture mandis are being connected online. So far, agricultural commodities valued at about Rs. 36 thousand crore have been traded on e-NAM portal.

The work of completing 99 Irrigation projects that were held up for decades is in progress.

Government is also protecting the interests of farmers by giving production bonus on pulses and oil seeds. As a result of Government's policy for pulses, their production went up by more than 38 per cent as compared to last year, which is a record.

To prevent damage to agriculture produce before it reaches the market and to ensure its safe storage, "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" has been launched. The supply chain and infrastructure in the agricultural sector are being modernized under this scheme.

To enhance the income of farmers, an ambitious scheme has been introduced in the Dairy sector under which a 'Dairy Processing Infrastructure Development Fund' with a corpus of Rs. 11 thousand crore is being set up.

While on one hand, my Government's policies have helped in increasing the production of urea, on the other, mandatory 100 per cent Neem coating of urea has eliminated its black marketing. The work on reopening of fertilizer plants at Gorakhpur, Barauni, Sindri, Talcher and Ramagundam is progressing at a fast pace.

**Honourable Members,** my Government is working actively and with sensitivity to remove the feeling of economic insecurity among the poor, farmers and senior citizens.

Under 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana', farmers are being provided affordable and simple crop insurance services. During 2017, under Rabi & Kharif crops, 5 crore 71 lakh farmers were provided protective coverage under this scheme.



Similarly, my Government has introduced insurance schemes for the poor at a premium of 1 rupee per month and 90 paise per day. More than 18 crore poor have been covered under the 'Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana' and 'Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana' and about Rs. 2 thousand crore has been paid out as claims.

My Government is also committed towards social security of senior citizens. Under the 'Atal Pension Yojana', about 80 lakh senior citizens have benefitted.

**Honourable Members**, following the path of Ekatm Manav-vad (Integral Humanism) propounded by Deen Dayal Upadhyaya, my Government is developing mechanisms to ensure that benefits of development reach the poorest of the poor.

About 2 lakh 70 thousand Common Service Centres have been set up that provide digital services at low cost, even in the remotest areas of the country.

Under the 'Bharat Net Project', the Government is providing broadband connectivity to 2 lakh 50 thousand Gram Panchayats. In the first phase, more than one lakh Panchayats have already been connected. This project will play a major role in taking e-health, e-education, e-governance and e-commerce to each village of the country.

To illuminate the lives of the poor and to enable them to move forward on the path to development, my Government is providing electricity connections to 4 crore poor people under the "Saubhagya" Yojana.

To ensure that benefits of development reach all sections of society, my Government is actively pursuing the work of connecting all villages under the 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana'. As compared to 2014 when only 56 per cent of the villages had road connectivity, now more than 82 per cent villages mostly in far flung and inaccessible areas have been connected by roads. Our target is to provide road connectivity to every village by 2019.

To ensure availability of two square meals to every poor person, effective enforcement of National Food Security Act is necessary. The distribution of food grains at cheap rates under this Act is being made transparent and leakage proof in all States of the country.

**Honourable Members**, working for the upliftment and dignity of all weaker and deprived sections of society is my Government's priority.

My Government is sensitive towards the aspirations of every section of society and has introduced a Constitution Amendment Bill to provide Constitutional Status to the National Commission for Backward Classes.

A Commission has been constituted to examine the sub-categorization of backward classes so that the benefits of higher education and jobs can be availed by the most backward sections among the backward classes.

Minimum Support Price of several forest produce collected by the tribal people has been increased.

Lives of lakhs of people in tribal areas especially in the North East region are dependent on bamboo industry. Inclusion of bamboo in the category of tree had adversely affected livelihoods associated with it. Keeping in mind these difficulties, my Government has excluded bamboo from the category of tree. This has now provided freedom to cut, transport and use bamboo.

Adivasi Swatantrata Sangram Sangrahalayas are being established to honour the invaluable contribution of tribal communities in the independence struggle. Recently, the foundation stone of first such museum was laid in Kevadia, Gujarat on the banks of Narmada, near the Sardar Sarovar Dam. Proposals of Jharkhand, Madhya Pradesh, Chattishgarh, Andhra Pradesh, Kerala, Manipur and other States are also under consideration.

**Honourable Members,** there are more than 2 crore 50 lakh Divyang jan in our country. My Government is continuously working with utmost sensitivity towards their empowerment and economic inclusion. Government has enacted the 'Rights of Persons with Disabilities Act 2016'. Provision has been made for 4 per cent reservation in government jobs and 5 per cent reservation in higher education for Divyang jan. In the last three years, over 6 thousand camps have been organised benefitting more than 9 lakh needy Divyang jan with necessary aids and assistive devices.

**Honourable Members,** committed to "Empowerment and not Appeasement", my Government is making intensive efforts for economic, social and educational empowerment of the minorities.

Employment opportunities have been provided to the youth belonging to Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi and Jain communities through programmes, such as, 'Seekho Aur Kamao', 'Ustad', 'Garib Nawaz Kaushal Vikas Yojana', 'Nai Roshni' etc.

More than 45 lakh students have also benefitted from scholarships, fellowships, skill development and coaching schemes during the last one year.

Keeping in mind the objective of womens' empowerment, for the first time since independence, the restriction on women above 45 years of age to perform Haj pilgrimage unaccompanied by their male

relatives has been removed. This year, more than 1300 women are going on Haj pilgrimage without Mehram.

**Honourable Members,** with a sensitive approach towards providing housing with availability of water-electricity-toilet facility to all, my Government is targeting to provide a house to every poor and homeless household by the year 2022.

Over the last three and a half years, more than 93 lakh houses have been constructed by the Government in rural and urban areas. Under the ‘ Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban’ , interest subvention of 6 percent is being provided to the poor. In addition, for the first time, two new schemes have been launched keeping the middle class in mind.

**Honourable Members,** one of the major worries of the poor and middle class relates to treatment of diseases. The financial burden of treatment of disease further aggravates the suffering.

A new ‘National Health Policy’ has been formulated by my Government for providing better and affordable healthcare facilities to the poor and middle class. In addition, under the ‘National AYUSH Mission’, traditional methods of treatment, such as, Yoga and Ayurveda are being promoted. It gives me pleasure to share with you that:

- Through the ‘Pradhan Mantri Jan Aushadhi’ Kendras, 800 different medicines are being made available to the poor people at affordable rates. More than 3 thousand such kendras have been established in the country.
- Under the ‘Deendayal Amrut Yojana’, over 5200 lifesaving branded medicines and surgical implants are being provided through 111 outlets at discounts ranging from 60 per cent to 90 per cent.
- In addition to medicines for heart patients, the cost of stent has been reduced up to 80 percent. The cost of knee implant has also been regulated.
- Under the ‘Pradhan Mantri National Dialysis Programme’, in over 500 districts, more than 22 lakh dialysis sessions for 2.25 lakh patients have been conducted at discounted rates.
- To enhance the availability of doctors, 7 thousand post graduate seats and over 13 thousand MBBS seats have been approved.
- To ensure quality and transparency in medical education, Government has also introduced the ‘National Medical Commission Bill’ in the Lok Sabha.
- I am happy to inform that the annual rate of increase in immunization coverage in the country has increased from 1 percent to 6.7 percent. This has benefitted children living in far-flung and particularly tribal areas of our country. Recently, my Government has also launched the ‘Intensified Mission Indradhanush’.

**Honourable Members,** education provides the foundation for building the future of the Nation. My Government is committed to strengthening and modernising School and Higher Education system in the country.

My Government has approved over 2400 'Atal Tinkering Labs' under 'Atal Innovation Mission', in order to inculcate a spirit of entrepreneurship and creativity in children at an early age.

My Government has approved setting up of a 'National Testing Agency' as an autonomous and self-sufficient organization to conduct all examinations of higher educational institutions in the country.

To ensure a bright future for the youth, my Government is working actively towards setting up of 20 'Institutes of Eminence'. Under this Mission, selected public sector institutions will be provided financial assistance of Rs.10 thousand crore.

A law has also been enacted to provide autonomy to all 'Indian Institutes of Management' in order to upgrade them further.

**Honourable Members,** our country is the youngest among all nations in the world. My Government is implementing programmes like Start Up India, Stand Up India, Skill India Mission, Mudra Yojana to provide self-employment to the youth and to enable them to fulfill their dreams.

My Government has recently approved two schemes – 'SANKALP' and 'STRIVE' for skill development of youth in line with the needs of the industry.

Enterprises or companies creating new employment opportunities are being provided financial assistance under the 'Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana'. Over 20 lakh people have benefited under this scheme.

About 5 lakh youth have benefitted under the 'National Apprenticeship Promotion Scheme'.

Our workers play a central role in Nation Building. Sensitive towards safeguarding their interests, my Government is continuously working for reforms in Labour laws.

My Government has increased the minimum wage of workers by more than 40 per cent. The number of registers for compliance of Labour laws has also been reduced from 56 to 5. All returns are now filed online on the Shram Suvidha Portal.

**Honourable Members,** excellence in sporting arena is viewed as an indicator of progress in the world. Alive to all round development of youth, my Government is working towards registering an effective presence in sports on the world stage.

In recent months, International Sports Competitions like FIFA Under-17 World Cup and Asian Athletic Championship have been successfully organized in the country. This has not only enhanced the prestige of the country in the sports arena but has also increased attraction towards sport disciplines like Football.

My Government has started an ambitious campaign namely 'Khelo India Programme' with an outlay of over Rs. 1750 crore.

For transparent selection of talented sportspersons, a 'Sports Talent Search Portal' has been started.

A scheme has been launched to provide stipend of Rs. 6 lakh per annum to one thousand talented sportspersons.

**Honourable Members,** the cultural heritage of our country is a part of our identity and provides the foundation for 'Ek Bharat- Shreshtra Bharat'.

It is a matter of pride for us that recently Kumbh Mela was included in the list of 'Intangible Cultural Heritage of Humanity'. Last year, UNESCO has accorded Ahmedabad the status of India's first 'Heritage City'. Chennai, on account of its glorious tradition of music, has been included in the list of Creative Cities by UNESCO.

It is my Government's continuous endeavor to preserve and protect our historical heritage through programmes such as 'Swadesh Darshan' and 'Amrut Yojana'.

**Honourable Members,** our Space Programme contributes immensely in providing right information in a timely manner to farmers, fishermen, students, scientists, thus contributing to the development of the country. Towards this end, India's ambitious space programme is accomplishing new heights in promoting national development and in furthering regional and international cooperation.

For the first time in the world, 104 Satellites were launched successfully at one go by ISRO.

In June 2017, the first developmental flight of India's GSLV MK-III was successfully launched which marked an important step in taking forward the launch capability of the country.

Last year on 5<sup>th</sup> May, ISRO launched the South Asian Satellite which demonstrated India's commitment towards sharing benefits of its technical capabilities with neighbouring countries.

This year on 12<sup>th</sup> January, ISRO made the country proud by successfully launching the PSLV-C40. On this day, ISRO also scored a century of satellites launched.

**Honourable Members,** in this modern era of digital connectivity, my Government is continuously working towards ensuring that our countrymen and future generations are able to harness the power of digital technology. The Digital India Mission is proving to be a milestone in providing due recognition and in securing the rights of the poor and deprived.

My Government is implementing the largest Digital Literacy Programme of the world under the 'Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharata Abhiyan'. So far, one crore people have been made digitally literate.

'BHIM App' is playing a major role in promoting digital transactions. The recently launched 'Umang App' has made more than 100 public services available on mobile phones.

'Aadhar' has helped in securing the rights of the poor by eliminating middlemen. At present, Digital Payments are being carried out in more than 400 schemes of the Government. As a result, it has become possible to provide Government benefits to the genuine beneficiaries. Till now, more than Rs. 57 thousand crore have been prevented from going into the wrong hands.

As a result of commendable efforts in the field of electronic manufacturing, the number of mobile companies in the country have gone up from a mere 2 in 2014 to 113. This has helped in providing new employment opportunities to our youth in small towns of the country.

**Honourable Members,** digital and physical connectivity play a big role in country's balanced development. My Government is striving towards enhancing connectivity and is equipping the transport sector to meet the challenges of the 21<sup>st</sup> century. Modern transport arrangements are being developed in a manner that different modes complement each other.

Railways remain the main mode of transport even today and that is why investment in Railways for capacity development and modernization is being enhanced continuously. My Government is committed to the construction of world class Railways. Work on Mumbai-Ahmedabad High speed bullet train has commenced.

My Government has formulated a new Metro Rail Policy which lays emphasis on 'last mile connectivity'. Presently, Metro work is in progress in 11 cities of the country.

Recently, my Government has approved an ambitious programme for development of highways namely 'Bharatmala'. A provision of Rs. 5 lakh 35 thousand crore has been made for this. Under this project, in order to enhance National Corridor Efficiency, about 53 thousand km. of National Highways have been identified.

Under 'Jalmarg Vikas Pariyojana', major projects on Ganga river have started in Varanasi, Sahibganj, Farakka and Haldia.

Under the 'Sagarmala programme', works on Special Economic Zone in Jawaharlal Nehru Port Trust and 'Smart Port Industrial Cities' in Paradip and Deen Dayal Port Trust have been taken up.

To provide air connectivity to smaller cities and to enable the lower middle class, middle class and young people to fly, "Ude Desh ka Aam Nagrik" or 'UDAN' scheme has been launched. While only 76 airports of the country were connected with commercial flights since Independence, under the aegis of 'UDAN', work has been initiated to connect 56 airports and 31 helipads in a short span of 15 months. So far, flights have commenced from 16 such airports.

Along with improving connectivity, these schemes are also generating new employment opportunities.

**Honourable Members**, for the first time, increase in Power generation capacity in the country has exceeded the target. Today, India has become a net exporter of power.

My Government has ensured power availability to States at cheap rates by completing work on the 'One Nation, One Grid'. Schemes worth Rs. 1.5 lakh crore have been implemented to strengthen the power distribution network in all villages and towns of the country. The work of electrifying 18 thousand villages is also nearing completion.

As of now, more than 28 crore LED bulbs have been distributed under 'UJALA scheme' and the private sector has also sold over 50 crore LED bulbs. This has resulted in an annual saving of over Rs. 40 thousand crore in the electricity bills for poor and middle class. In addition to conserving the environment, this has also resulted in an annual saving of 10 thousand crore units of electricity to the nation.

Mission to save electricity and efforts to increase electricity production are moving hand in hand. In last three years, solar energy generation has increased by seven times.

With Indian efforts, the International Solar Alliance has now become a legal entity. Its headquarter has been set up in India.

**Honourable Members**, with the objective of taking the benefits of development to every part of the country, my Government is working with sensitivity towards achieving the hopes and aspirations of the people of North-East.

To accelerate the pace of development of this area, North East Special Infrastructure Development Scheme has been sanctioned recently, with 100 percent central assistance. Under this scheme, projects relating to drinking water supply, energy, education and health will be completed.

To strengthen electricity transmission and distribution network in the North Eastern States, Government has sanctioned schemes worth Rs. 10 thousand crore in the last three years.

In Mizoram, a Hydro Electric Power Project constructed at a cost of Rs. 913 crore has been dedicated to the nation recently.

My Government is also striving to enhance road connectivity in the North-East.

Work on Agartala-Akhaura rail-link which will connect India and Bangladesh is progressing rapidly.

Shillong –Tura road project was dedicated to the people last year in December. This road will improve connectivity in the entire North-East region.

Last year, the longest river-bridge of the country- Dhola-Sadiyaa- was also dedicated to the nation. This bridge has reduced distance between Assam and Arunachal Pradesh by 165 kilometers.

My Government has also decided to develop the Barak River as National Waterway-16.

**Honourable Members**, due to regular efforts of the Central and State Governments, there has been a significant improvement in internal security of the country. The North East has also witnessed an improvement in the security situation. There has been a reduction in incidents of Naxal-Maoist violence. For this, the enlightened citizens of the region, our military, paramilitary and police forces deserve to be congratulated. We commend all our security personnel and pay heartfelt tribute to the martyrs.

Terrorist violence in the interiors of Jammu & Kashmir is directly related to cross-border infiltration. With better coordination, our Army, Para-Military Forces and Jammu-Kashmir Police are giving a befitting response to the perpetrators.



My Government has kept open the path of dialogue with those who wish to shun violence and join the main stream, while reposing faith in the Constitution of India. In the past three years, maximum number of youth influenced by the Naxal-Maoist ideology, have surrendered and joined the main stream.

My Government has also recently sanctioned a scheme of more than Rs. 18 thousand crore for the modernization of Police Forces.

The policy related to Strategic Partnership in Defence Manufacturing sector has also been given a final shape. This will encourage maximum participation of private sector in the manufacture of major defence platforms and equipment and would provide a fillip to employment generation.

My Government has fulfilled its commitment of 'One Rank One Pension' and disbursed arrears of more than Rs. 10 thousand crore to over 20 lakh retired armed forces personnel.

**Honourable Members,** service to humanity is an integral part of India's cultural heritage. Because of these values, India has always remained the First Responder in times of crises, such as the earthquake in Nepal, flood calamity in Sri Lanka and drinking water crisis in Maldives.

Today, all Indians residing in any corner of the world are confident that in case of a crisis, their Government will provide them with a safe passage to the country. More than 90 thousand Indians stranded abroad have been safely brought back since 2014.

Due to the successful diplomatic efforts of my Government, there has been a new found respect for India. As a result, India has been able to secure representation in the International Tribunal for the Law of the Sea, International Maritime Organization and Economic and Social Council. In a keenly contested election to the International Court of Justice, India emerged victorious.

Subsequent to inclusion in the Missile Technology Control Regime last year, India has been inducted as a member in the Wassenaar Arrangement and Australia Group this year. This success has come after a long wait and with prolonged efforts and is an important achievement of my Government.

The commencement of operations at Chabahar Port is a historic event. First shipment of wheat has been sent to Afghanistan through this Port. An Air-corridor between India and Afghanistan has been made operational this year and shipment of freight has started.

Ties with Indian Diaspora are being progressively strengthened. On 9<sup>th</sup> January this year, on the occasion of 'Parvasi Bhartiya Divas', a Conference of Parliamentarians of Indian origin was organized for the first time in which elected representatives from 24 countries participated.

The Ministry of External Affairs, in collaboration with Department of Posts, has embarked upon a comprehensive programme for expansion of Passport services in the country. Under this programme, establishment of 251 Passport Service Kendras has been announced, of which 60 centres have started functioning.

**Honourable Members,** to consolidate the foundation of development in the country, my Government has taken up the strengthening of financial institutions on priority.

As a result of this, India's growth rate remained impressive despite global economic slow-down. During the first quarter of 2016-17, the economy witnessed a temporary slowdown in GDP growth. The second quarter of 2017-18, however, has seen a reversal of this trend. In the last 3 and a half years, the rate of inflation as well as Government's fiscal and current account deficits have, on an average, shown a decline.

In 2017, Foreign Exchange Reserves have risen to a level of more than US dollar 410 billion. Appropriate policies adopted by my Government have contributed to an increase in Foreign Direct Investment from US Dollar 36 billion to US Dollar 60 billion during the last three years.

**Honourable Members,** with a view to resolving the problems of citizens, my Government has accorded priority to simplification of procedures. In the last three years, 1428 obsolete laws have been repealed and this is a continuous process.

Working towards achieving robust and inclusive development, my Government is striving to institutionalize honesty and develop transparent systems in the country.

To achieve economic integration of the country, my Government has introduced GST which is the biggest tax-reform since Independence. My Government has also constituted the National Anti-profiteering Authority so that benefits of lower prices of goods and services are passed on to the consumers.

My Government is also committed to revitalizing the banking system and to make it transparent. It has been decided to re-capitalise the public sector banks by infusing more than Rs. 2 lakh crore of capital in them.

Our fight against corruption continues. Towards this end, registration of about 3 lakh 50 thousand dubious companies has been cancelled in the last one year.

To bring transparency in government procurement and to provide opportunity to maximum number of entrepreneurs, a new system - Government E-market place has been created by the name of GeM. With the help of GeM portal, even the smallest of entrepreneurs are now capable of selling their products to Government.

To give preference to Make in India in public procurement, a new policy has been formulated. This policy promotes domestic manufacturing and services which in turn would create new opportunities for employment.

The Central Government is working together with States for creating a favourable business environment.

As a result of these efforts of my Government, India has moved up from 142<sup>nd</sup> to 100<sup>th</sup> rank in the *Ease of Doing Business* ranking of the World Bank. This has improved the credibility of the country in the global market.

**Honourable Members,** the effort of my Government is to achieve welfare of the people through public participation. My Government is taking feedback by communicating with the youth, women, farmers, entrepreneurs, students, workers and also from the people of civil society. Their suggestions are being incorporated in the policies and decisions of the Government.

**Honourable Members,** citizens alive to the state of governance in the country are concerned about the frequent elections in one part of the country or another, which adversely impact the economy and development. Frequent elections not only impose a huge burden on human resources but also impede the development process due to the promulgation of the model code of conduct. Therefore, a sustained debate is required on the subject of simultaneous elections and all political parties need to arrive at a consensus on this issue.

**Honourable Members,** Nation building is a continuous process in which each citizen of the country has a role to play. It is our responsibility to exhibit exemplary conduct before the nation. The completion of time bound goals towards Nation Building is our collective responsibility.

Attaining these goals by 2022, when the Nation celebrates the 75<sup>th</sup> year of Independence, would not only fulfil the dream of our freedom fighters and founding fathers but also strengthen the foundation of New India.

Dream of a New India does not belong to one political party or organization. It is an embodiment of the aspirations and expectations of 1 hundred 30 crore countrymen. To fulfil this dream, we all have to work together with complete dedication.

Come, let us all work towards achieving the ideals of equality and fraternity enshrined in our Constitution. Let us move ahead together in one direction with full commitment and energy towards creating a glorious India.

**Jai Hind!**

